



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

विनिर्माण हब: एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण

28 अप्रैल, 2026

मुख्य बातें

- बड़े पैमाने पर उत्पादन, विश्वसनीयता और लंबे समय तक चलने वाली औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, विनिर्माण नीति अब इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित, एकीकृत हब विकास की ओर मुड़ गई है।
- केंद्रीय बजट में 3 केमिकल पार्क, 7 पीएम मित्र (MITRA) पार्क, एमएसएमई क्लस्टर और ₹10,000 करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति (SHAKTI)' का प्रस्ताव रखा गया है।
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014-15 के ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान) में ₹12.2 लाख करोड़ हो गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा मिला है।
- एमएसएमई, जिनमें 7.47 करोड़ उद्यम शामिल हैं, की विनिर्माण उत्पादन में 35.4% हिस्सेदारी है और पूरे देश में विनिर्माण हब की रीढ़ हैं।

परिचय

विनिर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी स्तंभ है, जो जीडीपी में लगभग 16-17 प्रतिशत का योगदान देता है और 27 मिलियन से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देता है। जैसे-जैसे देश 2047 तक \$3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से \$30-35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है, विनिर्माण से इसमें एक अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है और इस तरह, जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर कम से कम 25 प्रतिशत हो जाएगी।

इस संदर्भ में, भारत की विनिर्माण रणनीति ने तेजी से एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग हब के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है-ये ऐसे स्थानीय इकोसिस्टम हैं जो भौतिक बुनियादी ढांचे, नियामक सहायता, साझा सुविधाओं और कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ते हैं। इन हब को बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने, लेन-देन की लागत को कम करने और लंबे समय तक चलने वाली विनिर्माण गतिविधियों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे घरेलू और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के भीतर भारत की स्थिति मजबूत होती है।

बदलते वैश्विक संदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग हब

आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह देखा गया कि वैश्विक विनिर्माण में एक ढांचागत बदलाव आ रहा है, जिसमें प्रतिस्पर्धा कम लागत वाले उत्पादन से कम, बल्कि विश्वसनीयता, लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता से ज्यादा तय होती है। जैसे-जैसे उत्पादन प्रक्रियाएं ज्यादा प्रौद्योगिकी-प्रधान और व्यवस्था-निर्भर होती जा रही हैं, स्थिर और एकीकृत विनिर्माण माहौल में काम करने की क्षमता, लंबे समय तक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का एक अहम कारक बनकर उभरी है।



जो देश स्थिर उत्पादन माहौल मुहैया करा पाते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कौशल और संस्थागत तालमेल का सहारा मिलता है; और वे विनिर्माण गतिविधियों को जारी रखने तथा लंबे समय तक उत्पादन के दायित्वों को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।

इस वैश्विक बदलाव और जारी औद्योगिक गति को, उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण की ओर बढ़ते रुझान और जीवीसी (वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं) के भीतर रणनीतिक अनिवार्यता पर बढ़ते जोर से मजबूती मिली है। जैसे-जैसे विनिर्माण ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी-प्रधान और व्यवस्था-निर्भर होता जा रहा है, यह तैयारी, उत्पादकता और विस्तार करने की क्षमता के महत्व को रेखांकित करती है। ऐसे विनिर्माण हब जो साझा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला के जुड़ाव और लॉजिस्टिक्स

एक वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से जुड़े चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक चरण कुछ न कुछ मूल्य जोड़ता है और कम से कम दो चरण अलग-अलग देशों में होते हैं।

कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत इकोसिस्टम प्रदान करते हैं, वे कंपनियों को बड़े पैमाने पर काम करने, मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठने और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में ज्यादा प्रभावी ढंग से एकीकृत होने में सक्षम बनाते हैं।

भारत के औद्योगिक विनिर्माण का सफर

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण में एक ढांचागत बदलाव आया है, जिसमें अब ध्यान परियोजना-स्तर के काम से हटकर सिस्टम-स्तर की योजना बनाने पर केंद्रित हो गया है। इस तरह की सिस्टम-स्तर की योजना, रुकावटों को कम करके, लॉजिस्टिक्स की क्षमता को बढ़ाकर और समय पर काम पूरा करने में मदद करके, विनिर्माण केंद्रों की प्रभावशीलता को सीधे तौर पर बढ़ाती है।

वैश्विक निवेश के रुझान अब भारत को विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पहचानने लगे हैं। इस समय, दुनिया भर में विनिर्माण के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली जगहों में इस देश का तीसरा स्थान है। इसके साथ ही, उत्पादन की बनावट में भी बदलाव आ रहा है; कुल विनिर्माण मूल्य-वर्धन में मध्यम और उच्च-तकनीकी गतिविधियों का हिस्सा 46.3% है, जो अधिक उन्नत औद्योगिक ढांचों की ओर हो रहे धीरे-धीरे बदलाव का संकेत देता है।

India's Manufacturing Capability



Key Indicators

- » Manufacturing value added: **~12.5% of GDP**
- » Share of medium-and high-technology manufacturing: **46.3%**
- » Global manufacturing growth momentum (Q1 2025): **6th among top 10 manufacturers**
- » Competitive Industrial Performance (CIP) Rank: **37th (2023)**
- » Global Innovation Index (GII) Rank: **38th (2025)**



Sources: Economic Survey 2025-26, UNIDO

भारत के विनिर्माण हब का परिदृश्य

पूरे देश में विनिर्माण हब का परिदृश्य एक बहु-स्तरीय इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुआ है, जो पैमाने, क्षेत्रीय जरूरतों और स्थानिक योजना में अंतर को दर्शाता है। किसी एक मॉडल का पालन करने के बजाय, नीतिगत हस्तक्षेपों ने विनिर्माण हब के विविध रूपों का समर्थन किया है। आज का विनिर्माण परिदृश्य बड़े एकीकृत पार्कों, क्षेत्र-विशेष इकोसिस्टम, एमएसएमई क्लस्टरों और कॉरिडोर से जुड़े औद्योगिक नोड्स से मिलकर बना है; इनमें से प्रत्येक को विशिष्ट उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और वैल्यू-चेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

विशाल एकीकृत विनिर्माण हब

ये सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा मौजूद है और जो प्रमुख निर्माताओं और उनके आपूर्तिकर्ता इकोसिस्टम को एक ही स्थान पर समाहित करते हैं। ये साझा यूटिलिटीज, रसद और सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन और लागत के लिहाज से किफायती उत्पादन संभव हो पाता है। ये पार्क बहु-क्षेत्रीय या क्षेत्र-आधारित हो सकते हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से या औद्योगिक गलियारों के भीतर विकसित किया जा सकता है।

प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर: उपयोग के लिए तैयार सुविधाएं, जो सेटअप में लगने वाले समय और लागत को कम करती हैं; इससे उद्योग तेज़ी से अपना परिचालन शुरू कर पाते हैं और निवेश पर जल्द रिटर्न प्राप्त कर पाते हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) एक बदलाव लाने वाली पहल है, जिसे पूरे भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि देश को एक वैश्विक विनिर्माण हब के तौर पर स्थापित किया जा सके। अब तक, भारत सरकार ने 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है, जो 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 13 राज्यों में फैले हुए हैं। इनमें से 4 औद्योगिक स्मार्ट सिटी-धोलेरा (गुजरात), शेंद्रा-बिडकिन (महाराष्ट्र), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और उज्जैन (मध्य प्रदेश) के पास विक्रम उद्योगपुरी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप-पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी 16 अलग-अलग चरणों में विकसित की जा रही हैं। इन औद्योगिक नोड्स को 'प्लग-एंड-प्ले' इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया जा रहा है।

पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) बड़े एकीकृत विनिर्माण हब हैं, जिन्हें विशेष रूप से टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला के लिए तैयार किया गया है। ये हब एक ही पार्क के दायरे में प्रसंस्करण, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और साझा सुविधाओं को एक साथ लाते हैं। इन पार्कों की घोषणा सात राज्यों में की गई है, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

क्षेत्र-विशेष विनिर्माण इकोसिस्टम

कुछ विनिर्माण क्षेत्रों को विशेष और पूंजी-गहन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे इकोसिस्टम-आधारित विनिर्माण हब जरूरी हो जाते हैं। ये हब पूरी मूल्य श्रृंखला को समर्थन देने के लिए उत्पादन इकाइयों को आपूर्तिकर्ता नेटवर्क, परीक्षण, नियामक और कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करते हैं।

- **बल्क ड्रग पार्क योजना:** यह योजना गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने में सहायता कर रही है, ताकि विश्व-स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा बनाकर बल्क ड्रग विनिर्माण की लागत को कम किया जा सके। ये पार्क दक्षता और पर्यावरणीय अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए साझा सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनमें सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट और साझा अपशिष्ट उपचार प्रणाली शामिल हैं।
- सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) 2.0** के तहत सहायता दी जाती है, जिसमें फैब्रिकेशन, असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग शामिल हैं। इन हब्स को अहम सेक्टरों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने और साथ ही वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **बायोफार्मा शक्ति** (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए हेल्थकेयर में प्रगति की रणनीति) की घोषणा की गई है, जिसके तहत अगले 5 सालों में ₹10,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा, ताकि भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब के तौर पर विकसित किया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विनिर्माण क्लस्टर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम का एक मुख्य आधार हैं, जिनका क्षेत्रीय स्तर पर विनिर्माण हब्स पर काफी असर पड़ता है। एमएसएमई की विनिर्माण आउटपुट में 35.4% हिस्सेदारी है, ये निर्यात में 48.58% का योगदान देते हैं और जीडीपी का 31.1% हिस्सा बनाते हैं; ये आंकड़े भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इनकी अहम भूमिका को दिखाते हैं।

एमएसएमई सेक्टर में 7.47 करोड़ से ज्यादा उद्यम शामिल हैं और इसमें 32.82 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिससे यह खेती के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा जरिया बन गया है। इतने बड़े पैमाने पर होने के कारण, एमएसएमई विनिर्माण हब के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में, जहां अक्सर एक जैसे कौशल, स्थानीय आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और कम लागत के फायदों के आधार पर क्लस्टर बन जाते हैं।

- सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) एमएसएमई क्लस्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाने और प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में मदद करता है। एमएसई-सीडीपी के तहत, कुल 580 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें 227 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) और 353 इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (आईडी) परियोजनाएं शामिल हैं।

- इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) पूरे देश में इंडस्ट्रियल एस्टेट, क्लस्टर, पार्क और जोन की मैपिंग करता है।
- राज्य औद्योगिक विकास निगम एमएसएमई के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं।

कॉरिडोर से जुड़े औद्योगिक केंद्र

इन हब मॉडलों के पूरक के तौर पर कॉरिडोर-आधारित औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो केवल अलग-थलग उत्पादन इकाइयों के तौर पर काम करने के बजाय एक व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में काम करते हुए, स्थानिक एकीकरण और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर जोर देते हैं। ये कॉरिडोर मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर, माल ढुलाई कनेक्टिविटी और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्रीकरण संभव हो पाता है।

ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर एक उच्च-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 'कैचमेंट' क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना है जिन्हें विभिन्न विकास परियोजनाओं के बीच साझा किया जाता है; इसे आमतौर पर स्थानीय सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य लाइनों का विकास शामिल है, जैसे कि जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवरेज/सेप्टेज, सड़कें, स्ट्रीटलाइट, बिजली आदि।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी), अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) और विशाख-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) जैसे औद्योगिक गलियारे, कनेक्टिविटी में सुधार करके और विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत योजना को सुगम बनाकर, विनिर्माण हब और क्लस्टरों को सहायता देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

राज्य की क्षमता और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन

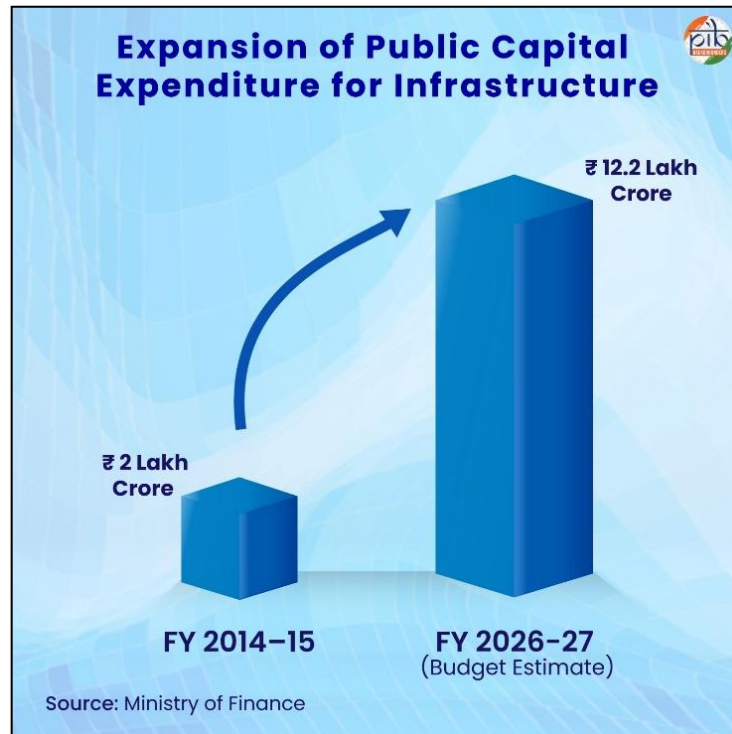
विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर हब का प्रदर्शन कुल मिलाकर जमीन अधिग्रहण, मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और नियामकीय मंजूरी देने में राज्य की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए, क्रियान्वयन और समन्वय को मजबूत करना हाल की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति पहलों का एक मुख्य केंद्र रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने और उसे लागू करने में आने वाली समन्वय संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए, सरकार ने 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत मंच है जो 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा और परियोजनाओं को एक साथ लाता है। यह पहल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की समन्वित योजना बनाने में मदद करती है, जिसमें मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, अंतिम-मील संपर्क और समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण को मजबूत करने के लिए, हाल के वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार का पूंजीगत परिव्यय वित्त वर्ष 2014-15 के ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹12.2 लाख करोड़ के बजट अनुमान तक पहुंच गया है। इस लगातार बढ़ोतरी ने बड़े विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए जरूरी भौतिक आधार को मजबूत किया है, जिसमें औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और माल ढुलाई कनेक्टिविटी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय क्या है?

जब सरकार स्कूल, अस्पताल, इमारतें, सड़कें, पुल, नहरें, रेलवे लाइनें आदि जैसी संपत्तियां बनाने के लिए खर्च करती है, या अपनी देनदारी कम करती है (जैसे कि ऋण का पुनर्भुगतान), तो ऐसे खर्च को पूंजीगत व्यय कहा जाता है।



परियोजना की तैयारी और उसे लागू करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत तंत्र भी शुरू किए गए हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को ट्रांज़ैक्शन सलाहकारों को फ़ाइनेंस करके सहायता देता है, ताकि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं विकसित की जा सकें जिन्हें बैंक से फ़ाइनेंस मिल सके; इससे एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित

प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी के लिए संस्थागत तैयारी का आकलन करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलमेंट इंडेक्स (एनआईआईआई) विकसित किया गया है।

इन उपायों से विनिर्माण हब के लिए अनुकूल माहौल बेहतर हुआ है। पूरे देश में राज्य-स्तरीय पहलें अलग-अलग क्षेत्रों और इलाकों में विनिर्माण हब के विकास को दर्शाती हैं:

- उत्तर प्रदेश, रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ सहित छह जगहों पर एक रक्षा औद्योगिक गलियारे (डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) विकसित कर रहा है।
- तमिलनाडु, जिसे 'एशिया का डेट्रॉइट' भी कहा जाता है, ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्लस्टर का विस्तार किया है, जिन्हें खास औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग मिला है।
- गुजरात बड़े पैमाने पर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और बंदरगाहों से जुड़े विनिर्माण हब्स का लगातार लाभ उठा रहा है।

वहीं, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे औद्योगिक गलियारे, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल से किए गए काम को और भी बेहतर ढंग से दिखाते हैं; इनमें औद्योगिक केंद्र संयुक्त संस्थागत ढांचों और अलग-अलग चरणों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर विकसित किए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर हब के लिए नीतिगत सहायता और बजट घोषणा

हाल के वर्षों में नीतिगत ढांचा एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विनिर्माण पर केंद्रित रहा है। यह इस बात को मानता है कि लगातार औद्योगिक प्रतिस्पर्धा केवल फर्म-स्तर के हस्तक्षेपों पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, समन्वय और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

यह रणनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, पीएम-मित्र पार्क, पीएम-गति शक्ति, डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म (जैसे यूएलआईपी), क्षेत्र-विशेष क्षमता-निर्माण उपायों, और औद्योगिक गलियारों, पार्कों और क्लस्टरों के विकास जैसी मिशन-उन्मुख पहलों में झलकता है। ये पहलें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को संस्थागत सहायता के साथ जोड़ती हैं। कुल मिलाकर, इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं, वित्तपोषण में देरी और समन्वय की कमी को कम करना है, जिन्होंने पहले औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को सीमित कर रखा था।

केंद्रीय बजट 2026-27 विनिर्मापार्कों, साइरा सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्रित सहायता के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विनिर्माण को आगे बढ़ाकर इसकी नींव रखता है। यह बजट विनिर्माण के लिए हब-आधारित

दृष्टिकोण को और मजबूत करता है, जिसमें पैमाने, विश्वसनीयता और मूल्य श्रृंखलाओं के बीच मजबूत जुड़ाव पर जोर दिया गया है।

2026-27 की प्रमुख बजट घोषणाएं: विनिर्माण हब	
सेक्टर/क्षेत्र	घोषणा
रसायन	क्लस्टर-आधारित रसायन निर्माण को मजबूत करने के लिए तीन नए रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें साझा सुविधाएं, सुरक्षा ढांचा और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
वस्त्र उद्योग	पहले से मंजूर किए गए 7 पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्कों को लागू करना जारी रहेगा, जिनका मकसद बड़े, एकीकृत टेक्सटाइल विनिर्माण हब बनाना है।
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विनिर्माण क्लस्टर	क्लस्टर-आधारित मैनुफैक्चरिंग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) को मजबूत बनाना, ताकि एमएसएमई को साझा उत्पादन, टेस्टिंग और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद मिल सके।
पूंजीगत वस्तुएं / औद्योगिक सहायक बुनियादी ढांचा	घरेलू पूंजीगत सामान और औद्योगिक विनिर्माण क्षमता को मजबूत बनाने के लिए टूल रूम, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन सुविधाओं को सहायता देना।
विनिर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचा योजना	औद्योगिक और विनिर्माण मैनुफैक्चरिंग जगहों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की समन्वित, मल्टीमॉडल प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति को लागू करना जारी रखना।
वैश्विक बायोफार्मा और विनिर्माण केंद्र: बायोफार्मा शक्ति	बायोफार्मा-केंद्रित विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने के लिए पांच सालों में ₹10,000 करोड़ का आवंटन, जिसमें तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) और 1,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का देशव्यापी नेटवर्क शामिल है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उम्मीद है कि लगातार आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने में विनिर्माण एक अहम भूमिका निभाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट,

इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के ज़रिए मैनुफैक्चरिंग को मजबूत बनाने में नीतिगत समर्थन और सार्वजनिक निवेश के महत्व को दिखाते हैं।

इस रणनीति का एक अहम हिस्सा टियर-2 और टियर-3 शहरों पर बढ़ता फोकस है, जहां विनिर्माण हब को कम लागत, स्थानीय कौशल और बेहतर कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे क्षेत्रों पर लगातार ज़ोर देना—जिसे सरकार की समन्वित नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का समर्थन हासिल हो—यह पक्का करने के लिए जरूरी होगा कि विनिर्माण-आधारित विकास व्यापक, मजबूत और भारत के लंबे समय के विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

<https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-11/IIID%20Policy%20Brief%2015%20-%20Manufacturing-led%20growth.pdf>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114840®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1734169®=3&lang=2>

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3656_ISj6wd.pdf?source=pqals#:~:text=1.97%20lakh%20crore%20to%20enhance,been%20placed%20at%20Annexure%20I

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2081537®=3&lang=2>

वित्त मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219990®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221443>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2219991®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2221458®=1&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219992®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219984®=20&lang=1>

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT)

<https://www.dpiit.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/industrial-corridors-YjM2UDNtQWa>

<https://pmgatishakti.gov.in/pmgatishakti/login#:~:text=The%20National%20Master%20Plan%20will,terms%20of%20time%20and%20cost.&text=Individual%20Ministries%20and%20Departments%20often.coordination%20of%20work%20between%20them.&text=The%20plan%20will%20provide%20the.visibility%20to%20the%20executing%20agency.&text=All%20Ministries%20and%20Departments%20will,and%20updating%20the%20master%20plan.>

शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)

https://nios.ac.in/media/documents/SrSec318NEW/318_Learner_guide_eng/318_LG_E_L29.pdf

गुजरात सरकार

<https://www.vibrantgujarat.com/invest-gujarat>

तमिलनाडु सरकार

https://spc.tn.gov.in/wp-content/uploads/TN_AUTOMOTIVE_FUTURE.pdf

उत्तर प्रदेश सरकार

<https://invest.up.gov.in/defence-aerospace-sector/>

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF)

<https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india>

<https://www.ibef.org/government-schemes/pm-gati-shakti-yojana>

<https://www.ibef.org/blogs/changing-india-s-industrial-environment-an-overview-of-the-national-industrial-corridor-development-programme-nicdp>

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

[https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf#:~:text=\(SLNA\)%20Nodal%20Agency%20designated%20by%20the%20State/UT,between%20developments%2C%20commonly%20provided%20by%20local%20governments](https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf#:~:text=(SLNA)%20Nodal%20Agency%20designated%20by%20the%20State/UT,between%20developments%2C%20commonly%20provided%20by%20local%20governments)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522®=3&lang=1>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1982305®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1911134®=3&lang=2>

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक

<https://indiaindustrialandbank.gov.in/exploreParkReport>

नीति आयोग

[https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-](https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-04/India_Hand_Power_Tools_Sector_Report.pdf)

[04/India_Hand_Power_Tools_Sector_Report.pdf](https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-04/India_Hand_Power_Tools_Sector_Report.pdf)

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम

<https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/integrated-industrial-township-vikram-udyogpuri>

वस्त्र मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2117663®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205530®=3&lang=2>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224376®=3&lang=2>

काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (COSIDICI)

<https://www.cosidici.com/>

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/एमपी